

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सचिव,
विधि विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 02.3.17

विषय:- भवन निर्माण विभाग के माध्यम से विधि विभाग द्वारा आवंटित कार्यों की अद्यतन समीक्षात्मक टिप्पणी के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 11848(भ)अनु० दिनांक 07.12.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में कहना है कि विधि विभाग के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु 186 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इन कार्यों की माह जनवरी, 2017 तक की प्रगति की स्थिति निम्नवत है:-

(1) भौतिक प्रगति:-

- कुल 186 योजनाओं में से 116 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है, जिसका विवरण अनुलग्नक के परिशिष्ट 'क' पर द्रष्टव्य है।
- 33 कार्य प्रगति में है, जिसकी विवरणी परिशिष्ट 'ख' पर द्रष्टव्य है।
- 21 योजनाएं निविदा/प्राक्कलन/मिट्टी जांच के चरण में है, जिसकी विवरणी परिशिष्ट 'ग' पर द्रष्टव्य है।
- 07 योजनाओं के लिए स्थल समस्या है एवं 06 का कार्य स्थगित है, जिसकी विवरणी परिशिष्ट 'घ' पर द्रष्टव्य है।
- 03 योजनाओं का कार्य निगम द्वारा कराया जा रहा है, जिसकी विवरणी परिशिष्ट 'च' पर द्रष्टव्य है।

(2) वित्तीय प्रगति:-

- वित्तीय वर्ष 2016-17 में माँग संख्या-3 में कुल ₹29367.00 लाख का बजट उपबंध है, जिसके विरुद्ध ₹4343.86 लाख रुपये का व्यय किया जा चुका है।

(3) प्रशासी विभाग के ध्यानाकर्षण हेतु मुख्य मुद्दे:-

- विधि विभाग के द्वारा नई योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता है बजट उपबंध अधिक है एवं स्वीकृत योजनाओं की संख्या उस अनुपात में कम है। जिस कारण से बजट उपबंध रहने के बावजूद योजना व्यय कम है।

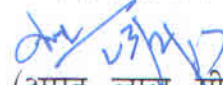
- पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति हेतु लंबित योजनाओं पर शीघ्र पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाए।
- जिन योजनाओं के लिए स्थल अनुपलब्ध है, उनमें शीघ्र स्थल उपलब्ध कराया जाए।
- अदालतगंज, पटना परिसर में उच्च न्यायालय पटना के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवास का निर्माण हेतु राशि की आवश्यकता है। तदनुसार निधि उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

(4) अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की व्यवस्था

- भवन निर्माण विभाग के स्तर पर आपके विभाग की योजनाओं के अनुश्रवण के लिए श्री रविन्द्र नाथ प्रसाद, उपनिदेशक-1 को दायित्व दिया गया है जिनका ई-मेल dd1.bcd@gmail.com तथा मोबाईल नं० 9431049735 है।
- भवन निर्माण विभाग द्वारा Project Management Information System विकसित किया गया है, जो विभाग के वेबसाईट पर उपलब्ध है। इस अनुश्रवण व्यवस्था में सभी योजनाओं की अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय स्थिति Upload करायी जा रही है। आपसे अनुरोध है कि प्रशासी विभाग के स्तर से भी योजनाओं की प्रतिवेदित भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा की जाए। इस क्रम में किसी बिन्दु पर इस विभाग के स्तर से कार्रवाई अपेक्षित हो तो कृपया अवगत कराया जाए।
- उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय पदाधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक में भी इस समीक्षा टिप्पणी में अंकित बिन्दुओं पर समीक्षा की जाएगी। उस बैठक में अद्यतन विवरणी के साथ स्वयं या नोडल पदाधिकारी को भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्त करने की कृपा की जाए।
- विभाग द्वारा विकसित PMIS पर योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रशासी विभाग भवन निर्माण के वेबसाईट पर जाकर आईडी-LAW एवं पासवर्ड-LAW का उपयोग कर विधिवत जानकारी लिया जा सकता है।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन


(अमृत लाल मिश्रा)

सरकार के प्रधान सचिव।

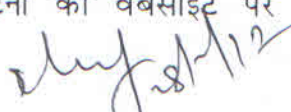
ज्ञापांक- पी०एम०यू०-बी०सी०डी०-14/2016...1828.../पटना, दिनांक 2.3.17

प्रतिलिपि:-संयुक्त सचिव/अभियन्ता प्रमुख के प्रावैधिकी सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक (अनुश्रवण)।

ज्ञापांक- पी०एम०यू०-बी०सी०डी०-14/2016...1828.../पटना, दिनांक 2.3.17

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


निदेशक (अनुश्रवण)।